(D) मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (iv) अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली एवं राजसमन्द के 14 प्रखण्ड

(v) शाहबाद व किशनगढ़ प्रखण्डों की सहरिया जनजाति निवासियों के लिए

कूट :

(a) A-(iv) B- (iii) C- (v) D-(ii)
(b) A-(i) B-(ii) C-(iii) D-(iv)
(c) A-(ii) B-(i) C-(v) D-(iii)
(d) A-(i) B-(iv) C-(ii) D-(iii)

उत्तर – (b)

RPSC RAS/RTS 2008

व्याख्या – मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1987-88) – अलवर जिले के 8 ब्लाक व भरतपुर जिले के तीन ब्लाक।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – चार जिलों के 13 खण्ड
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1999-95) – 21 पंचायत समितियों की 357 ग्राम पंचायत
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (2000-01) – अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पाली एवं राजसमन्द के 14 प्रखण्ड।

1693.राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन् में प्रारंभ हुआ?

(a) 1960-61 (b) 1977-78 (c) 1982-83 (d) 1994-95

उत्तर – (b)

RPSC RAS/RTS 2008

व्याख्या – मरु विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना तथा मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है। 1999 से इस योजना में राज्य सरकार भी सहयोग देने लगी अर्थात् 75 : 25 का दोनों का योगदान है।

1694. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ?

(a) 2 अक्टूबर, 2011
(b) 31 अक्टूबर, 2011
(c) 14 नवम्बर, 2011
(d) 19 नवंबर, 2011

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिग्रीधारक)-18.05.2022

Ans. (c) : राजस्थान लोक सेवाओं में प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 को 14 नवम्बर 2011 से लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आम जनता से जुड़े 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी दी गयी है। इन विभागों का कोई अधिकारी या कर्मचारी अधिनियम की परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नहीं करता है तो कम से कम 500 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 रूपये तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया गया है।

1695. निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की?

(a) सुन्दर सिंह भण्डारी योजना
(b) स्मार्ट वर्क स्कीम
(c) सबको काम योजना
(d) स्वास्थ्य बीमा योजना

RPSC Computer Exam-2018 Date 07-10-2022

Ans. (a) : राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में सुंदर सिंह भण्डारी योजना जारी की। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रूपये ऋण राशि के रूप में मिलेंगे। ऋण राशि पर 4% वार्षिक दर से ब्याज चुकाना होगा।

1696. आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है-

(a) 3.50 लाख (b) 4.00 लाख
(c) 4.50 लाख (d) 3 लाख

RPSC RAS (Pre) 2021

Ans. (c) : 30 जनवरी, 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एकीकरण करते हुए आयुष्मान-भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के तहत साधारण बीमारी हेतु लाभार्थी परिवारों को 50 हजार रुपये तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख रुपये तक बीमा कवरेज रहेगा।

1697. राजस्थान में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है?

(a) मुख्यमंत्री कार्यालय
(b) उद्योग निदेशालय
(c) आयोजना विभाग
(d) मानव संसाधन विकास विभाग

RPSC RAS (Pre) 2021

Ans. (c) : राजस्थान में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजन विभाग (State Planning Department) को नोडल विभाग घोषित किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों में निहित 17 लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015-2030 तक की अवधि में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

1698. 2021-22 के राजस्थान-बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है-

(a) 52.19% (b) 14.32%
(c) 7.42% (d) 12.05%

RPSC RAS (Pre) 2021

Ans. (b) : राजस्थान बजट में 2021-22 में विद्युत पर कुल व्यय 19449 करोड़ रुपये प्रस्तावित था जिसमें से योजनागत व्यय पर लगभग 8.4% खर्च किया जाना सुनिश्चित किया गया। राजस्थान में निर्धनता,बेरोजगारी , विकास कार्यक्रम समाज कल्याण चिकित्सा एवं स्वस्थ्य।

1699. राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में, घोषित आई एम शक्ति 'उड़ान' योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए-

(a) इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवम्बर, 2021 से सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे।
(b) यह योजना 19 नवम्बर, 2021 से लागू होगी।
(c) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर दो और जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसेडर बनाए जायेंगे